प्रेस विज्ञप्ति

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने रिटेल डिवीजन, एलिवेटिंग रूफटॉप सोलर के लिए विजन का अनावरण किया

नई दिल्ली, 20 फरवरी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), श्री प्रदीप कुमार दास ने हाल ही में शुरू किए गए "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" के बारे में अपने संबोधन के दौरान रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की बैंकेबिलिटी बढ़ाने के लिए एजेंसी के सक्रिय रुख को स्पष्ट किया ।" उन्होंने रूफटॉप सोलर, पीएम-कुसुम, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी) सेगमेंट को शामिल करने वाली खुदरा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक रिटेल डिवीजन स्थापित करने के लिए इरेडा की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की।

इरेडा के सीएमडी , आज सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा विदेश कार्य मंत्रालय की साझेदारी में आयोजित "दूसरे सीआईआई इंडिया यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव" के हिस्से के रूप में "ग्रीन फाइनेंसिंग: आर्किटेक्चर फॉर एक्सेसिबल फाइनेंस " के बारे में आयोजित पैनल चर्चा में बोल रहे थे । उन्होंने उल्लेख किया कि भारत सरकार की मंजूरी के अधीन, इरेडा खुदरा क्षेत्रों की जरूरतों को पूरी करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित कर सकती है।

यह चर्चा मुख्य रूप से विकास में तेजी लाने के लिए भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का समर्थन करने पर केंद्रित थी, जिसमें परियोजना बैंकेबिलिटी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। श्री दास ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बैंक योग्य बनाने के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें उभरती हुई इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड आदि शामिल हैं। उन्होंने बेहतर पारदर्शिता और उधारकर्ताओं की चिंताओं को निवारण करके पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने में इरेडा की सफलता की गाथा पर प्रकाश डाला।

श्री दास ने पर्यावरणीय स्थिरता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी रेखांकित किया। उन्होंने एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इरेडा के समर्पण की भी फिर से पुष्टि की। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर वित्तपोषण सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एमएसएमई को अपनी रेटिंग और प्रशासन में सुधार करने के महत्व पर जोर दिया।